सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या—cm-329
10/08/2017

मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, लघु जल संसाधन, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण एवं आपदा प्रबंधन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की

पटना, 10 अगस्त 2017 :— मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में भवन निर्माण विभाग तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की। मुख्यमंत्री ने कल अपराह्न में अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, लघु जल संसाधन एवं आपदा प्रबंधन विभाग की भी उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की थी। समीक्षा बैठक में संबंधित विभाग के सभी बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी। समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा—निर्देश दिये गये।

बैठक के उपरांत मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह ने लघु जल संसाधन विभाग की समीक्षा के संदर्भ में बताया कि लघु जल संसाधन विभाग के अधीन क्रियाशील योग्य कुल 9192 राजकीय नलकूप हैं, जिसमें 5040 नलकूप चालू हैं। इस वितीय वर्ष में शेष नलकूपों की मरम्मति कराकर चालू कराने का लक्ष्य है। राजकीय नलकूपों को चालू कराकर उन्हें कमांड क्षेत्र के व्यक्ति/संस्था (जीविका, पैक्स आदि) वगैरह को हस्तांतरित किया जायेगा। राजकीय नलकूपों को हस्तांतरित करने के पश्चात पटवन दर निर्धारित करने का अधिकार संचालक को ही दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि विभाग के अन्तर्गत अनुदान आधारित क्रियान्वित की जा रही बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के अन्तर्गत अब तक 10,479 निजी नलकूप लगाये जा चुके हैं।

मुख्य सचिव ने विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के समीक्षा के संदर्भ में बताया कि राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई0आई0आई0टी0) भागलपुर की स्थापना एवं सत्रारंभ भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कैम्पस में किया गया है, जिसमें 73 छात्रों का नामांकन हो चुका है। पटना में पूर्व राष्ट्रपति डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम के नाम पर साईंस सिटी का निर्माण किया जायेगा। दरभंगा जिला में तारामण्डल की स्थापना हेतु संशोधित परियोजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की जायेगी। उन्होंने बताया कि गया जिला में सब—रीजनल साईन्स सेंटर की स्थापना हेतु भारत सरकार के संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ साईन्स म्यूजियम (एन0सी0एस0एम0) के द्वारा निविदा इसी सप्ताह आमंत्रित की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा विभागीय समीक्षा के दौरान सात निश्चय कार्यक्रम को गति प्रदान करने के निदेश के अतिरिक्त नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करने हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी अन्तर्गत बिहार काउंसिल ऑन साईन्स एण्ड टेक्नोलॉजी को नोडल संस्थान के रूप में विकसित करने एवं नवप्रवर्तकों को व्यापक दृष्टिकोण के साथ उदारतापूर्वक प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि बिहार सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र द्वारा किये गये कार्यों की विस्तृत समीक्षा के उपरांत इस संस्थान को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के अद्यतन ऑकड़े को हर वर्ष तैयार करके सभी संबंधित विभाग को स्वतः प्रदान करने का निदेश दिया गया। इस

हेतु सभी आवश्यक उपकरणों एवं मानव संसाधन को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। बिहार सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित डाटा संवर्द्धन एवं अद्यतीकरण हेतु आने वाले सभी राशि का वहन विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा करने का निदेश दिया गया।

मुख्य सचिव ने अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग की समीक्षा के संदर्भ में बताया कि छात्रों के लिये स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के साथ–साथ अन्य सभी छात्रवृति की योजनायें भी जारी रहेगी। प्रवेशिकोतर छात्रवृति योजना के तहत वर्ष 2015–16 के पूर्व के नामांकित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को नामांकन के वर्ष से सक्षम प्राधिकार द्वारा नामांकन के समय निर्धारित फीस की देय छात्रवृति की राशि का भुगतान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि एकलव्य मॉडल के तहत निर्माण कराये जा रहे आवासीय विद्यालयों को भी 720 मॉडल के आवासीय विद्यालय के अनुरूप भारत सरकार से प्राप्त राशि के अतिरिक्त शेष राशि का प्रावधान राज्य स्कीम से किया जायेगा।

मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा के संदर्भ में बताया कि राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (एस0ई0ओ0सी0) को बेली रोड, पटना अवस्थित नवनिर्मित भवन में माह दिसम्बर 2017 तक स्थानांतरित कर दिया जायेगा, इसके लिये ऑपरेशनल मैनुअल, मानव संसाधन एवं अन्य उपकरणों के क्रय की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि वज्रपात से बचाव हेतु पूर्व चेतावनी प्रणाली के विकास हेतु ऑध्रप्रदेश राज्य के अनुरूप कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रणाली के तहत वज्रपात की घटना के आधा घंटा पूर्व जानकारी मिल सकेगी।

मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह ने भवन निर्माण विभाग की समीक्षा के संदर्भ में बताया गया कि भवन निर्माण विभाग को विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही महत्वपूर्ण योजनायें यथा– विधानसभा एवं सचिवालय विस्तारीकरण, सम्राट अशोक कन्वेंशन केन्द्र, बिहार संग्रहालय, पुलिस भवन, मॉडल विधायक आवासन योजनान्तर्गत बिहार विधान पार्षद आवास एवं बिहार विधानसभा सदस्य आवास, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, गया, पी0एम0सी0एच0 स्थित आई0जी0आई0सी0 का निर्माण, पटना उच्च न्यायालय विस्तारीकरण पर सभी आवश्यक दिशा–निर्देश देते हुये कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं यथा– साईन्स सिटी का निर्माण, वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, नई दिल्ली में बिहार सदन, आदि के संबंध में आवश्यक निदेश देते हुये इस पर अविलम्ब सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब यह निर्णय लिया गया है कि भवन निर्माण प्रस्ताव में भवन निर्माण के साथ–साथ भवनों के फर्निसिंग का भी प्रावधान होगा।

भागलपुर घटना के संबंध में मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि भागलपुर में सरकारी राशि के गबन का बड़ा मामला सामने आया है। मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 302 करोड़ रूपये का गबन का मामला है। ई0ओ0यू0 की टीम मामले में जॉच कर रही है। उन्होंने बताया कि मामले में सरकार के खाता से पैसे को ट्रांसफर किया गया था। इस पूरी प्रक्रिया में सृजन संस्थान एवं बैंकों की मिलीभगत है। जिलाधिकारी के गलत हस्ताक्षर करके पैसे निकाले गये। मामले में अब तक तीन एफ0आई0आर0 दर्ज किये जा चुके हैं। सृजन महिला संस्थान, बैंक के पदाधिकारी, सरकारी कर्मी जो खाते एवं उसके दस्तावेज की देख–रेख करता था, पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

******